भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3335

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

पीएसबी का औसत ऋण-जमा अनुपात

3335. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का औसत ऋण-जमा अनुपात (सीडीआर) कितना रहा है; और

(ख) ऋण आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): दिनांक 31.3.2024, 30.6.2024 और 30.9.2024 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात क्रमशः 75.8%, 76.5% और 76.5% हैं।

इसके अलावा, आरबीआई ने बैंकों को भिन्न-भिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच के अनुपात में व्यापक विषमता न होने देने को सुनिश्चित करने की सलाह दी है ताकि ऋण प्रदान करने में क्षेत्रीय असंतुलन कम-से-कम हो और बैंक ऐसे क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा कर सके तथा ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। जिला के अग्रणी बैंक सीडी अनुपात के कम होने की समस्या से संबंधित सभी पहलुओं पर बैंको के साथ और साथ ही जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) फोरम में विचार-विमर्श कर सकते हैं। डीसीसी की विशेष उप-समितियाँ (एसएससी) को 40% से कम सीडी अनुपात वाले जिले में सीडी अनुपात को बढ़ाने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट तिमाही आधार पर डीसीसी के समक्ष और उनके द्वारा राज्य स्तरीय संयोजक को प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण आउटरीच योजनाओं पर सक्रियतापूर्वक कार्य करना, क्षेत्र-विशिष्ट उधार देना, सामुदायिक सहभागिता, सरलीकृत ऋण आवेदन प्रक्रिया, रणनीतिक साझेदारी, सरकारी निकायों के साथ सहयोग शामिल हैं।

******